(b) if so, the damage caused to India's own fishing wealth and fishing industry as a result thereof;

(c) whether labour unions and coastal States have demanded cancellation of all these licences; and

(d) whether Government propose to accede to this demand and if so, by when?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI DILIP KUMAR RAY): (a) There are 15 valid charter permits as on 15.7.96 and only 4 vessels out of these are in operation.

(b) There is no scientific data/report to the effect that chartered vessels have caused damage to Indian fishing wealth and fishing Industry. It has been found that the catch from these vessels, being less than 0.5% of the total marine production in 1995, is too small a proportion to pose such a threat.

(c) Fishermen's groups and some coastal State Governments have demanded cancellation of charter permits, joint venture/leasing permissions etc.

(d) The Government had constituted a Review Committee to make recommendations for review of the deeo sea fishing policy. This Review Committee has submitted its report and one of its recommendations is that charter permits may be cancelled, subject to legal processes as may be required. Action has been initiated at inter-Ministerial level to examine these recommendations.

बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना

503. श्री एस॰एस॰ सुरजेवाला:
श्री अजीत जोगी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी को देश में पूर्ण स्वामित्व आधार पर इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए अनुमोदित किया है और यदि निर्यात करने की अनिवार्य शर्त से भी छूट दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आम इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के उद्योगों और टी॰ वी॰ मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन इंडिया के प्रतिनिधियों ने इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित न करने का कोई अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस संबंध में मौजूदा नीति की समीक्षा करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र के॰ अलघ): (क) और (ख) औद्योगिक नीति पर दिनांक 24 जुलाई, 1991 को सदन के पटल पर रखा गया वक्तव्य विदेश पूंजीनिवेश का स्वागत करता है जो देश के औद्योगिक विकास के हित में है तथा इससे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, विपणन में विशेषज्ञता, आधुनिक प्रबंधकीय तकनीकों के प्रवर्तन तथा निर्यात संवर्धन की नयी संभावनाओं के सहायक लाभ प्राप्त होते हैं। विदेशी साम्य पूंजी का निवेश नीति में निर्धारित सिद्धांतों तथा सरकार की पूर्व अनुमति की शर्तों के अधीन है। तदनुसार, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र से संबंधित मामलों को अनुमोदित किया है।

(ग) उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी तथा टीवी विनिर्माता संघ (सेटमा) ने उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय व्यापारिक कम्पनियों को अनुमति देने तथा निर्यात की किसी बाध्यता के बिना सत-प्रतिशत विदेशी साम्य पूंजी वाली कम्पनियों को अनुमति देने के लिए सितम्बर 95 में अभ्यावेदन किया था।

(घ) और (ङ) इलेक्ट्रॉनिकी के क्षेत्र के लिए विदेश पूंजीनिवेश के बारे में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्राप्त प्रस्तावों पर विदेशी पूंजीनिवेश से संबंधित सरकार की सामान्य नीति के अनुसार कार्रवाई की जा रही है;

Application of Agri-Electronic Instruments

504. SHRI SURINDER KUMAB SINGLA: Will the Minister of SCIENCE AND TECHNOLOGY be pleased W state:

(a) whether it is a fact that the Agf" electronic instrrraents developed by th^|